

भारत सरकार  
अंतरिक्ष विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 622

गुरुवार, 07 दिसंबर, 2023 को उत्तर देने के लिए

देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

622. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार क्या है और इसमें सरकारी और निजी संस्थाओं की हिस्सेदारी कितनी-कितनी है;
- (ख) विगत पांच वर्षों में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हुई है;
- (ग) क्या सरकार देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार रखती है, यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) आगामी वर्षों में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार क्या होगा और इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका कितनी होगी; और
- (ङ) अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय  
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री  
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार लगभग 8.4 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। इसमें से डाउनस्ट्रीम सेवा बाजार, जोकि मुख्य रूप से संचार और डेटा अनुप्रयोगों को शामिल करता है, कुल अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 80% के करीब है, जिसमें निजी क्षेत्र एक प्रमुख योगदानकर्ता है। अपस्ट्रीम बाजार, अर्थात् उपग्रह और प्रक्षेपण प्रचालन, जिसमें मुख्य रूप से सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है और उप-प्रणालियों/ घटकों के निर्माण और वितरण की दिशा में निजी क्षेत्र की विक्रेता उन्मुखी भूमिका होती है।
- (ख) विभिन्न बाजार सर्वेक्षणों के अनुसार, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8% के औसत सीएजीआर के साथ बढ़ी है।

...2/-

...2...

(ग) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं :

- 1) अंतरिक्ष क्षेत्र का उदारीकरण किया गया है और निजी क्षेत्र को आद्योपांत अंतरिक्ष गतिविधियां आयोजित करने की अनुमति दी गई है।
- 2) अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) की गतिविधियों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और उनकी देखरेख के लिए अंतरिक्ष विभाग में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) बनाया गया।
- 3) भारतीय अंतरिक्ष नीति - 2023 जारी की गई है, जिसमें समग्र भारतीय अंतरिक्ष परितंत्र में योगदान करने वाले सभी हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित की गई हैं।
- 4) निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और ठोस सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं, अर्थात् बीज निधि योजना, मूल्य निर्धारण सहायता नीति, मेंटरशिप सहायता, गैर सरकारी कंपनियों के लिए डिजाइन प्रयोगशाला, अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास आदि की भी घोषणा की गई और इन्हें इन-स्पेस द्वारा लागू भी किया गया।

(घ) भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्षित आकार वर्ष 2033 तक लगभग 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अपेक्षित आंकड़े प्राप्त करने में निजी क्षेत्र की मुख्य भूमिका होगी। यह उम्मीद की जाती है कि निजी क्षेत्र उपग्रह निर्माण, प्रमोचन रॉकेट निर्माण, उपग्रह सेवाएं प्रदान करने और भूस्थित प्रणाली निर्माण में स्वतंत्र रूप से आद्योपांत समाधान प्रदान करेगा।

(ङ) उपर्युक्त (ग) के अंतर्गत उठाए गए कदमों के अलावा, अंतरिक्ष स्टार्ट-अप में निवेश वर्ष 2019 में 6 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2023 में 125 मिलियन अमेरिकी डालर (संचयी 370 मिलियन अमेरिकी डालर) से अधिक हो गया है। संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति अनुमोदन के अंतिम चरण में है, जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश को सक्षम बनाएगा।

\*\*\*